

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 322  
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

5जी प्रौद्योगिकी सेवाएँ

322. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहित देश के सभी जिलों में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू कर दी गई है।
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और 5जी प्रौद्योगिकी सेवाओं से कौन-कौन से लाभ प्राप्त होंगे;
- (ग) यदि नहीं, तो सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
- (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त परियोजना के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) आंध्रप्रदेश राज्य के सभी जिलों में 5जी सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। इसके अलावा देशभर में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क शुरू किया जा चुका है और वर्तमान में देश के 770 से अधिक जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक 4.6 लाख से अधिक 5जी बेस टांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें आंध्रप्रदेश के 18,730 बीटीएस शामिल हैं।

5जी सेवाओं के लाभों में पिछले 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक पीक डेटा रेट, कम लेटेंसी और उच्च स्पेक्ट्रम कार्यक्षमता शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।

- ii. वित्तीय सुधारों के परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), व्याज दरों और जुर्माना युक्तिसंगत हो गए हैं।
- iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, व्यापार और सरेंडर की अनुमति दी गई है।
- iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- v. दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च करने से आरओडब्ल्यू अनुमतियां को सुव्यवस्थित बनाया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए क्लीयरेंस प्रक्रिया में तेजी आई है।
- vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू नियमों में प्रावधान किया गया है।

31 अक्टूबर 2024 तक आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 18,730 5जी बीटीएस लगाए जा चुके हैं। 5जी सेल कवरेज की रेज कई कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें इस्तेमाल की जाने वाली फ्रिक्वेंसी बैंड, भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति, विकिरण शक्ति और क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व शामिल हैं। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में 90% से अधिक आबादी 5जी मोबाइल सेवाओं द्वारा कवर कर ली गई है।

\*\*\*\*\*